forming part of the 20-Point programme. Further, a scheme called 'three-tier scheme is being implemented by the States/UTs under which data on housing and building statistics are being collected. The data thus collected are compiled and published by the National Buildings Organisation periodically.

(c) The Seventh Plan document has recognised the importance of the involvement of non-governmetal organisations in housing activities who are expected to contribute with their local knowledge, skill and practical experience, to effectively meet the demand of the poor for affordable shelter. The Government have been encouraging non-governmental organisations for conducting research/studies in the field of housing and human settlements. HUDCO has also been encouraging the involvement of NGOs in their housing programmes in the rural and urban areas. Several housing schemes have been executed with HUDCO's financial assistance and cooperation from Lions, Rotaries, etc. The IYSH National Site and Shelter demonstration project at Madipur and Shahdra in Delhi for women as head of the households, as wsll as construction workers of EWs category has been formulated involving NGOs like All India Women's Conference and SEWA, etc.

Appointments of Correspondents

2819. SHRI PARVATHANENI UPENDRA; Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly twenty appointments of correspon dents have been stayed in Doordar shan; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) and (b) Yes, Sir. This is in pursuance of the decision on a petition filed before the Central Administrative Tribunal on 27-11-1987.

Foreign chartered and Joint Venture Fishing Boats

2820. SHRI SUBAS MOHANTY: Wiil the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to rescind its decision to keep foreign chartered and joint venture fishing boats away at least fifty miles from the Indian shore;

(b) if se, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that an Association of Large Trawler owners have been lobbying for chartering policy: and

(d) if so, the name of this association?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No decision has been taken by the Government to keep foreign chartered and joint venture fishing boats away at least fifty miles from trie Indian shore.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति और मल-व्ययन संस्थान में हुये घोटाले

2821. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति और मलव्ययन संस्थान में जिन घोटालों की जांच की जा रही है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त घोटालों में कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सीमेंट का आवंटन

2822. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के आयुक्त के कार्यालय में सीमेंट के आवंटन के लिए ओ. आर. सी. (दर ठेका श्रेणी से इतर) लाइसेंसधारियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जबकि निचले वर्ग की सोसायटियों और व्यक्तियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" है, तो उसके क्या कारण हैं क्या सरकार सीमेंट के आवंटन के लिए मान्यता-प्राप्त तथा पंजीकृत सोसायटियों को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और क्या पंजीकृत सोसायटियों को सीमेंट के आवंटन में किसी प्रकार की विसंगति सरकार के ध्यान में आई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच के ल भगत) : (क), जी नहीं । दिल्ली प्रशासन ने इस बारे में इन्कार किया है ।

(ख) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार दिल्ली प्रशासन के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा, सीमेंट नियंत्रक के परामर्श से सीमेंट विनिर्माता कम्पनियों से कहा जाता है कि वे दर ठेका श्रेणी से इतर सीमेंट की बिक्री हेतु अपने प्रतिष्ठित स्टाकिस्ट तथा वितरक नियुक्त करें । उसके पश्चात् विभाग, दर ठेका श्रेणी से इतर सीमेंट के प्रयोक्ताओं को सीमेंट उद्योग के क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा किये गये आवंटन के अनुसार सीमेंट बेचने के लिए स्टाकिस्टों को प्राधिकृत करता है । संबंधित सीमेंट विनिर्माता कम्पनियां अपने प्राधिकृत वितरकों को सीमेंट सप्लाई करती है, जो आगे गृह हाउसिंग सोसायटियों को सीमेंट सप्लाई करते हैं । इस मामले में दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है ।

स्मैक के व्यसनियों के लिए केन्द्र

2823. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी दिल्ली में स्मैक पीने वाले लोगों की आदत को रोकने के लिए एक केन्द्र खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के केन्द्र दिल्ली के पूर्वी भाग में और देश के अन्य राज्यों में भी खोले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो तो कब तक और यदि "नहीं" तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से उत्तरी दिल्ली सहित दिल्ली के विभिन्न भागों में सेवा प्रदान करने हेतु सात परामर्श केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा नशीली दवाओं के व्यसनियों के पुनर्वास के लिये एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं । चालू